फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 74 संख्याः 236 प्रभात जयपुर, शुक्रवार 29 मार्च, 2024 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

epaper.rashtradoot.com

राष्ट्रदूत

Rashtradoot Metro

Departed And So Remembered

"Here lies Marcus, Who never did anything but eat, drink and sleep. You may well ask, 'Why did he die then?'"

South Indian Breakfast

Whistled Languages

Whistled speech, used for public announcements and even courtship, mimics the tones and intonation of spoken languages.

सी.पी. जोशी दिन में चार बार निर्णय बदल चुके हैं भीलवाड़ा से चुनाव लड़ने के बारे में

प्रभारी रंधावा, डोटासरा, गहलोत, पूर्व विधानसभाध्यक्ष सी.पी. जोशी, विपक्ष के नेता जूली का पी.सी.सी. बैठक में यह अनिश्चय का नाटक देखा गया

- मूल समस्या है कि, जयपुर में बैठे गहलोत अभी भी राजस्थान कांग्रेस का संचालन कर रहे हैं तथा वे सी.पी. जोशी को अपना मुख्य साथी व सहयोगी बनाये हुए हैं।
- दोनों मिल कर यह ही प्रयास कर रहे हैं कि, किसी भी तरह सचिन पायलट के हाथ में डोर नहीं चली जाये। पायलट को येन-केन-प्रकारेण रोकना ही है।
- अब सवाल यह उठता है कि, गहलोत अभी भी कांग्रेस में अपनी बात कैसे मनवा पा रहे हैं। चर्चा है कि, यह इसलिये संभव हो रहा है कि, किन्ही कारणों से गहलोत का साथ दे रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे।
- और राहुल गांधी सी.ई.सी. की बैठक में या तो अनुपस्थित रहते हैं या कुछ बोलते नहीं।
- इन परिस्थितियों में जयपुर बैठक में कांग्रेस का ''कॉकस'' खुलकर कांग्रेस के उम्मीदवारों के चयन में अपनी चला रहा है।
- बहरहाल, भीलवाड़ा से दामोदर गुर्जर का टिकट बदलने का निर्णय लिया गया है। अजमेर में अस्सी वर्षीय राम चन्द्र चौधरी को बदलने का दबाव है, पर, डोटासरा उनको बदलने का जमकर विरोध कर रहे हैं।

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 मार्च। कांग्रेस नेतृत्व ने मन बना लिया है कि, दामोदर गूजर को बदला जाएगा और उनकी जगह भीलवाड़ा से किसी अधिक योग्य उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा।

जयपुर का ''कॉकस'' सी.पी. जोशी को भीलवाड़ा से प्रत्याशी बनाने के लिए प्रयास में जुटा है।

आज सुबह जयपुर पी.सी.सी. ऑफिस में एक बैठक हुई, जिसमें, रंधावा, डोटासरा, अशोक गहलोत, सी.पी. जोशी और कांग्रेस लैजिस्लेटिव पार्टी (सी.एल.पी.) के नेता जूली ने भाग लिया।

करीब ढाई घंटे से अधिक चली यह मीटिंग, सी.पी. जोशी को भीलवाड़ा से चुनाव लड़ने के लिए राजी करने के लिए आयोजित की गई थी। अंततः उन्होंने अनमने ढंग से स्वीकृति दे दी।

दिल्ली नेतृत्व चाहता है कि, जोशी लिखित में अपनी स्वीकृति दें, क्योंकि, इस मुद्दे पर जोशी ने ''कभी हाँ कभी ना'' का रुख अपनाया हुआ है।

रोचक है कि, शाम होने तक उन्होंने

(शेष पृष्ठ 4 पर)

केजरीवाल की हिरासत अवधि बढ़ी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 मार्च। गुरुवार को राउज़ एवेन्यु कोर्ट की स्पैशल जज कावेरी बवेजा ने दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एनफोर्समैंट डायरैक्टोरेट (ई.डी.) में हिरासत अवधि चार दिन के लिए और 1 अप्रैल तक बढ़ा दी। केजरीवाल की गिरफ्तारी दिल्ली के आबकारी नीति घोटाले को लेकर की गई है और वह नीति अब रद्द की जा चुकी है। ई.डी. ने केजरीवाल की हिरासत अवधि सात दिन के लिए और

- अरविन्द केजरीवाल एक अप्रैल तक ई.डी. की हिरासत में रहेंगे। इधर दिल्ली हाई कोर्ट से केजरीवाल को राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को मु.मंत्री पद से हटाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी।

(शेष पृष्ठ 4 पर)

'अतिक्रमण हटाना व चिन्हित करना सरकारी अधिकारियों का काम, वकील इसमें लिप्त ना हों'

राजस्थान हाई कोर्ट ने जयपुर शहर में अतिक्रमण पर लिए गए स्वतः संज्ञान मामले में आदेश पारित किये

- हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ के, हर जोन में अतिक्रमण के सर्वे के लिए वकीलों को नियुक्त किये जाने के आदेश को रद्द कर दिया है।

-यादवेंद्र शर्मा-

जयपुर, 28 मार्च। राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा जयपुर शहर से अतिक्रमण को हटाने के संबंध में लिये गये स्वतः संज्ञान के मामले पर आज सुनवाई हुई। अतिरिक्त महाधिवक्ता जी.एस. गिल ने अदालत को बताया कि सरकार अलग-अलग ज़ोन का सर्वे कर रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि कानून के अनुसार ही अतिक्रमियों को हटाया जाये। उन्होंने अदालत को बताया कि वर्ष 2014 के कानून के अनुसार राज्य सरकार ने ठेले और थड़ी वालों को पंजीयन कार्ड दिये हैं, सरकार केवल उन्हीं थड़ी और ठेलों को हटायेगी जिन्होंने अतिक्रमण किया है और जिनके पास सरकार द्वारा दिया गया पंजीयन कार्ड नहीं है।

मुख्य न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव व न्यायाधीश भुवन गोयल की खंडपीठ ने इस तथ्य पर बड़ी नाराजगी जताई कि एकलपीठ के अदालती आदेश के बाद हाईकोर्ट बार एसोसियेशन ने वकीलों की सूची जारी की जो शहर के हर ज़ोन में अतिक्रमण की गतिविधि पर निगरानी रखते हुए स्थानीय थाने को इस संबंध में सूचित करें। अदालत ने इस पर कठोर टिप्पणी करते हुए कहा कि अतिक्रमण को चिन्हित करना व हटाना केवल प्रशासनिक अधिकारियों का कार्यक्षेत्र है और इसमें वकीलों को लिप्त नहीं होना चाहिये।

इस मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से न्यायमित्र शोभित झांझड़िया की ओर से ज़ोन वाईज रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये समय मांगा गया, जिसके बाद अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद तय की है।

'पेपरलीक मामले में शीघ्र होंगी कई गिरफ्तारियाँ'

सूत्रों के अनुसार, एस.आई. पेपरलीक प्रकरण की जांच कर रही एस.ओ.जी. को इस संबंध में कई नए सबूत मिले हैं

- कई जैन्युइन अभ्यर्थियों ने एस.ओ.जी. में शिकायत दर्ज कराई और अपने सैंटरों में परीक्षा देने आए डमी कैंडिडेट्स की जानकारी दी, साथ ही उन प्रत्याशियों के बारे में भी बताया, जो एस.आई. चुने जाने की शैक्षणिक योग्यता नहीं रखते हैं।
- कुछ शिकायतों में तो यह भी जानकारी दी गई है कि, एक ही परिवार के लगभग 20 से 25 सदस्यों की पिछले चार या पांच सालों में ही सरकारी नौकरी लगी है, जबकि उसी परिवार के कई अन्य सदस्य पेपरलीक मामलों में या तो गिरफ्तार हो चुके हैं या संदिग्ध रहे हैं।

जयपुर, 28 मार्च (का.सं.)। सब इंस्पैक्टर भर्ती परीक्षा 2021 पेपरलीक प्रकरण में सूत्रों के अनुसार स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एस.ओ.जी.) का जांच का दायरा बढ़ाने के लिये कई नये सूत्र मिले हैं, जिसके चलते कुछ ही समय में कई गिरफ्तारियां भी देखने को मिल सकती हैं। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार एस.ओ.जी. को परीक्षा में भाग लेने वाले वास्तविक अभ्यर्थियों, जो पेपरलीक प्रकरण से पीड़ित हैं, की ओर से ऐसी शिकायतें व दस्तावेज दिये जा रहे हैं, जिनमें उनके सेंटरों पर संभावित डमी अभ्यर्थियों की जानकारी है साथ ही ऐसे फर्जी अभ्यर्थियों के बारे में भी बताया गया है जिनका पढ़ाई-लिखाई से कोई वास्ता नहीं था लेकिन फिर भी पास हुए है और उनका चयन किया गया।

कुछ शिकायतों में तो यह भी जानकारी दी गई है कि एक ही परिवार के लगभग 20 से 25 सदस्यों की पिछले चार या पांच सालों में ही सरकारी नौकरी लगी है, जबकि उसी परिवार से कई अन्य सदस्य पेपर लीक मामलों में या तो गिरफ्तार हो चुके हैं या संदिग्ध रहे हैं।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि पेपरलीक प्रकरण की जांच करने के लिये अब सामान्य वर्ग के वास्तविक अभ्यर्थियों की ओर से बड़ी स्पष्ट जानकारी दी जा रही है, जिसके चलते जल्द ही गिरफ्तारियां शुरू होंगी। इस अधिकारी ने आगे बताया कि शिकायतों के साथ

(शेष पृष्ठ 4 पर)

अमेरिका ने फिर से भारतीय मसलों पर टिप्पणी की

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 मार्च। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज़ करने के संदर्भ में अमेरिका के विदेश विभाग ने निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया की मांग को दोहराया है। भारत सरकार ने इन टिप्पणियों को अस्वीकार्य बताते हुए कहा है कि दूसरे देशों को भारत की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए।

विदेश मंत्रालय ने बुधवार को अमेरिका के एक वरिष्ठ राजनयिक को

- अमेरिका ने शुक्रवार को फिर से केजरीवाल की गिरफ्तारी पर चिंता जताई, साथ ही कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज़ करने पर भी टिप्पणी की। भारत सरकार ने अमेरिका की टिप्पणियों को अस्वीकार कर नाराजगी जताई।

(शेष पृष्ठ 4 पर)

बहुत गहरे मायने हैं जे.एन.यू. छात्र संघ चुनाव नतीजों के

गत सप्ताह सम्पन्न हुए चुनावों में सभी सीटों पर वामपंथी विजयी रहे हैं

- बारह साल में पहली बार जे.एन.यू. छात्र संघ चुनावों में सबसे ज्यादा, रिकॉर्ड 73 प्रतिशत मतदान हुआ है और 1996-97 के बाद पहली बार दलित अध्यक्ष चुना गया है।
- कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित इस युनिवर्सिटी के चुनाव नतीजे संभवतया इस बात का संकेत हैं कि, भारत के युवाओं का मौजूदा व्यवस्था से मोह भंग होने लगा है।

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 मार्च। पिछले सप्ताह 22 मार्च को देश के प्रतिष्ठित जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुए छात्र संघ चुनाव कोई सामान्य चुनाव प्रक्रिया नहीं थी और न ही यह एक सामान्य चुनाव था। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि 24 मार्च को घोषित परिणाम संकेत हैं कि भारत का युवा वर्ग संविधान व भारत का विचार तथा आंदोलन की स्वतंत्रता की विरासत पर आर.एस.एस.-भाजपा के हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार है।

अगले सप्ताह जे.एन.यू. के नाम वाली एक बॉलीवुड फिल्म प्रसारित की जा रही है। इस फिल्म के प्रचार वाले पोस्टर पर एक प्रमुख पंक्ति में पूछा गया है, क्या एक विश्वविद्यालय देश को तोड़ सकता है?

यह फिल्म एक तरह से जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय पर परोक्ष रूप से हमला है, यह विश्वविद्यालय भारत का एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक विश्वविद्यालय है, जो दशकों से राजनीतिक सक्रियता का गढ़ रहा है और इसमें प्रवेश देने का दायरा इस तरह से निर्धारित किया गया है ताकि देश के सबसे गरीब व मुख्यतः उपेक्षित क्षेत्रों के विद्यार्थियों को एक उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (जे.एन.यू. एस.यू.) के चुनावों में संयुक्त वाम पैनल के विद्यार्थियों को रविवार को भारी बहुमत से विजय प्राप्त हुई, इसने अपने सबसे करीबी प्रतिद्वंदी आर.एस. एस. से सम्बद्ध ए.बी.वी.पी. को चुनावों में मात दे दी और महत्वकांक्षी भारतीय युवाओं ने ए.बी.वी.पी. को खास तौर से संदेश दिया कि वे क्या चाहते हैं।

इन चुनावों में एक बात यह हुई कि चार साल के अंतराल के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ए.बी.वी.पी.) के उमेश सी. अजमीरा जिसे अध्यक्ष पद के चुनावों में 1676 वोट प्राप्त हुए थे उसके खिलाफ जे.एन.यू.एस.यू. के चुनावों में ऑल इंडिया स्टूडेन्ट्स एसोसिएशन के धनन्जय ने अध्यक्ष पद के चुनावों में सर्वाधिक 2598 वोट प्राप्त करके जीत दर्ज की है। धनन्जय बिहार में गया शहर के निवासी है और वर्ष 1996-97 में चुने गए बत्ती लाल बैरवा के बाद वाम विंग के पहले दलित अध्यक्ष हैं।

चुनावों में विजय प्राप्त करने के बाद बोलते हुए उन्होंने कहा, ''जे.एन.यू. के विद्यार्थियों ने इस विजय के माध्यम से यह मत व्यक्त किया है कि उन्होंने नफरत और हिंसा की राजनीति को खारिज कर दिया है। विद्यार्थियों ने एक बार पुनः हम पर विश्वास व्यक्त किया है। हम उनके अधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष करते रहेंगे तथा उन मुद्दों पर कार्य करेंगे जो उनसे ताल्लुक रखते हैं।

स्टूडेन्ट्स फैडरेशन ऑफ इंडिया (एस.एफ.आई.) के अविजित घोष ने उपाध्यक्ष पद के चुनाव में ए.बी.वी.पी. की दीपिका शर्मा को 927 वोटों के अंतर से परास्त कर दिया।

घोष को इस पद पर 2409 वोट प्राप्त हुए जबकि शर्मा को केवल 1482 वोट प्राप्त हुए थे।

बिरसा अंबेडकर फुले स्टूडेन्ट्स एसोसिएशन (बी.ए.पी.एस.ए.) की उम्मीदवार प्रियांशी आर्य, वाम विंग ने जिसका समर्थन किया था, ने महासचिव के पद पर ए.बी.वी.पी. के उम्मीदवार अर्जुन आनंद को 926 वोटों के अंतर से हरा कर करारी मात दी। आर्य के पक्ष में 2887 वोट गिरे जबकि आनंद को महासचिव पद पर केवल 1961 वोट प्राप्त हुए।

चुनाव होने से ठीक पहले मध्य रात्रि को 2 बजे विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा लेफ्ट प्रत्याशी स्वाति सिंह की उम्मीदवारी रद्द करने के बाद लेफ्ट ने जो तैयारी व तत्परता दिखाई, उससे यह ज्ञात होता है कि, वे इस खतरे के प्रति सजग थे।

चुनाव समिति द्वारा यूनाइटेड लेफ्ट की प्रत्याशी स्वाति सिंह की उम्मीदवारी को ए.बी.वी.पी. द्वारा चुनौती देने के बाद स्वाति नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया था उसके बाद यूनाइटेड लेफ्ट ने धनन्जय की उम्मीदवारी का समर्थन किया था।

वाम के मोहम्मद साजिद ने संयुक्त

(शेष पृष्ठ 4 पर)

द इकॉनमिस्ट का दावा, भारत के इस वर्ष के आम चुनाव विश्व के सबसे महंगे चुनाव होंगे

इस वर्ष चुनावों में 15 अरब डॉलर खर्च होने की संभावना है और 3.5 खरब की अर्थव्यवस्था के लिए यह जी.डी.पी. का मात्र 0.15 प्रतिशत है

- भारत के चुनावों में हमेशा से ही भारी धन राशि खर्च होती रही है। ब्लूमबर्ग बैंक के अनुसार वर्ष 2019 के भारतीय आम चुनावों में 8.6 अरब डॉलर खर्च हुए थे।
- इतने भारी खर्च को देखते हुए चुनाव में फंडिंग बड़ी समस्या रही है और अक्सर इसने विवादों को जन्म दिया है। वर्तमान में चल रहा इलैक्टोरल बॉण्ड विवाद भी इसी से संबंधित है।
- पूर्व में कॉरपोरेट कम्पनियां राजनैतिक दलों को खुले आम कानूनी रूप से चंदा देती थीं पर इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थीं तब उन्होंने इस पर रोक लगा दी थी, बाद में राजीव गांधी ने यह रोक हटाई।
- चुनाव फंडिंग के लिए वामपंथियों ने सरकार द्वारा पैसा देने का सुझाव रखा, पर यह भी सही नहीं माना गया था।
- वर्तमान में इलैक्टोरल बॉण्ड विवाद में भाजपा को सर्वाधिक चंदा दिए जाने का आरोप है, पर आश्चर्य की बात है कि, क्षेत्रीय दलों को उनकी सामर्थ्य से कहीं ज्यादा चंदा मिला है।

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 मार्च। निर्मला सीतारमण और उनके द्वारा इस वर्ष के शुरु में प्रस्तुत बजट के बारे में जब भी आपने सोचा होगा तो एक बात तो आपको माननी पड़ेगी की वह बहुत ईमानदार हैं। भारत सरकार के लाखों-करोड़ों रूपए के व्यय का प्रबंधन करने के बाद वित्त मंत्री ने स्वीकार किया कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं है।

वास्तव में, भारत में चुनावों में भारी धनराशि खर्च होती है और यह भी आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि चुनाव के कई दावेदार पानी के जैसे पैसा बहाते है। चुनावी फण्डिंग हमेशा से एक जटिल विषय रहा है और इसको लेकर बनी नीतियों में कई बदलाव होते आए हैं।

वास्तव में इसके लिए धन कहां से आता था। एक समय था जबकि इसमें कॉरपोरेट अंशदान वैधानिक रूप से जायज था और कॉरपोरेट्स से खुले तौर पर कानूनी रूप से चंदा देने की उम्मीद की जाती थी। इसे किसी अन्य ने नहीं बल्कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बंद कर दिया था। उन्होंने राजनीतिक पार्टियों और चुनावों में कॉरपोरेट अंशदानों पर प्रतिबंध लगा दिया था लेकिन बाद में उनके पुत्र राजीव गांधी ने ही यह प्रतिबंध हटा दिया।

पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने को लेकर कई प्रस्ताव किए गए। उनमें से एक में चुनावों की सरकारी फण्डिंग की बात थी, लेकिन उसे तुरन्त प्रभाव से इस आशंका से स्वीकार नहीं किया गया कि कहीं राजनैतिक पार्टियां सारे सरकारी धन को ही ना डकार जाए। आज भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया (मार्क्सवादी) इस प्रकार के सिस्टम की आकांक्षी बतायी जाती है।

वामपंथियों के अधिकांश सपनों की भांति यह भी एक अन्य दिवा स्वप्न है। वामपंथियों के महानतम नेताओं में से एक ई.एम.एस. नम्बूदरीपाद ने हिंदी भाषी क्षेत्रों में वामपंथी विचारधारा के प्रसार का सपना देखा था। भाजपा जहाँ धन को अर्जित करने पर प्रहार कर रही है, वहीं उसने इलैक्टोरल बॉण्ड्स को स्वीकार किया है, लेकिन हम इलैक्टोरल बॉण्ड के बारे में जितना भी कुछ जानते हैं, उस पर हुई कार्यवाही के साथ ही इलैक्शन फण्डिंग का रहस्य और गहरा गया है।

एक लॉटरी किंग ने सबसे अधिक इलैक्टोरल बॉण्ड्स खरीदे। वह किसे लाभ पहुंचा रहा है। यह अब तक स्पष्ट नहीं है।

यह समझ में आता है कि दक्षिण के लॉटरी किंग को दक्षिण भारत की कुछ लोकप्रिय पार्टियों को लाभांवित करना था, तो पूर्व में बिजली वितरण कम्पनी ने बॉण्ड्स खरीदे। उन्हें यू.पी. या छत्तीसगढ़ जैसे दूरस्त राज्य के बजाए कोलकाता में राजनीति के स्थानीय बॉस को लाभांवित करना था।

इलैक्टोरल बॉण्ड्स का सबसे बड़ा हिस्सा भाजपा के खाते में गया, लेकिन कुछ क्षेत्रीय प्रमुख नेताओं को भी इससे बड़ी धनराशि मिली। एक गणित समझिए। भाजपा को पूरे देश में 500 सीटों पर चुनाव लड़ना है। उसके पास

(शेष पृष्ठ 4 पर)

कोटा में एक और कोचिंग स्टूडैंट ने आत्महत्या की

कोटा, 28 मार्च (निसं)। कोटा में मैडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने आई उत्तरप्रदेश की छात्रा ने गुरुवार को आत्महत्या कर ली। छात्रा महावीर नगर प्रथम इलाके में पी.जी. में रहती थी। कोटा में तीन दिन में यह आत्महत्या का दूसरा मामला सामने आया है।

छात्रा की आत्महत्या की सूचना मिलने के बाद जवाहर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही फॉरेंसिक टीम भी मौके पर बुलाई गई। जवाहर नगर थाना अधिकारी कमलेश कुमार शर्मा ने बताया कि मृतक छात्रा उत्तरप्रदेश के लखनऊ की रहने वाली थी। छात्रा पिछले साल कोटा आई थी और वो नीट की तैयारी कर रही थी।

- मृतक छात्रा लखनऊ से नीट की तैयारी के लिए पिछले साल कोटा आई थी।

पुलिस ने छात्रा के परिजनों को सूचना दे दी है। परिजनों के आने के बाद ही छात्रा के शव का पोस्टमार्टम

(शेष पृष्ठ 4 पर)